(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) इसे स्वीकृति प्रदान करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना हैं ; और

(ङ) क्या किन्हीं अन्य राज्यों में भी नए इस्पात संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (घ) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत "लोहा और इस्पात" उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है तथा कुछ प्रतिबंधित स्थानों को छोड़कर इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से भी छूट दे दी गयी है । इसलिए नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं हैं । मध्य प्रदेश राज्य में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस की मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है ।

(ङ) देश के विभिन्न भागों में इस्पात उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए अनेक इकाइयों ने रूचि ली है। इनमें से 8 परियोजनाओं जिनमें 12240 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश किया गया है और जिनकी क्षमता 63.9 लाख टन वार्षिक है, का वित्तीय संस्थानों द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गयी है और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त 11935 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाली 10 और परियोजनाओं जिनकी क्षमता लगभग 68.4 लाख टन वार्षिक हैं, को वित्तीय संस्थानों को उनके मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

Bombay Urban Transport Project-II

2965. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the World Bank as also the State Government of Maharashtra had proposed that all the comprising suburban railway component related to the Bombay Urban Transport Project (BUTP-II) should be taken up integrally as part of BUTP-II;

(b) if so, whether Government did not agree to this proposal, and if so what are the specific reasons; and

(c) what other sources besides budgetary resources and World Bank assistance have been proposed and identified for financing the BUTP-II?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) As studies suggested by the World Bank are still in progress, the Govt. of India have not taken any decision in the matter.

(c) As no final decision has been taken, question does not arise at this stage.

Appointment of OBC candidates in CPWD

2966. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 11 candidates belonging to district Alwar, Bharatpur and Dosa (Rajasthan) who are having fake certificates of OBC were declared selected as Khallasi (Elect.) in December, 1994 by the concerned Superintending Engineer (Elect.) Coordination Circle (Elect.) New Delhi;

(b) whether it is also a fact that some M.Ps had also written to the